



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 30 पटना, बुधवार, 3 श्रावण 1940 (श0)  
25 जुलाई 2018 (ई0)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4-बिहार अधिनियम	---
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	4-4
पूरक	---
पूरक-क	5-7

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

जल संसाधन विभाग

आवश्यक सूचना

19 जुलाई 2018

विषय- लोअर किउल नदी घाटी योजना के आधुनिकीकरण अंतर्गत कुन्दर बराज निर्माण कार्य के तहत चालू खरीफ अवधि 2018 में दायां अंडर स्लूइस को तोड़कर निर्माण कार्य करने हेतु दायां मुख्य नहर में जलापूर्ति बंद रखने के संबंध में ।

सं० सि०को०-1/2001 पार्ट III-359--मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के परिक्षेत्राधीन लोअर किउल नदी घाटी योजना के आधुनिकीकरण अंतर्गत कुन्दर बराज निर्माण कार्य के तहत दायां अंडर स्लूइस को तोड़कर निर्माण कार्य करने हेतु खरीफ सिंचाई 2018 में दायां मुख्य नहर का जलश्राव बंद करने का निर्णय लिया गया है ।

अतः संबंधित नहरों के कमांड क्षेत्र के कृषकों से अनुरोध है कि चालू खरीफ सिंचाई 2018 हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे । उपरोक्त कार्य में आप सबों का सहयोग प्रार्थित है ।

आदेश से,

अरूण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

Home Department

(Police Branch)

NOTIFICATION

The 13<sup>th</sup> July 2018

No. 7/CCA-1026/2001 H(P) 6064--Consequent upon elevation of Hon'ble Mr. Justice Ajay Kumar Tripathi, Patna High Court as the Chief Justice of Chhattisgarh, High Court, who was Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 1981
2. National Security Act, 1980
3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974
- and
4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

Hon'ble Mr. Justice <b>Dr. Ravi Ranjan</b>	<b>Chairman</b>
Hon'ble Mr. Justice <b>Sri Aditya Narayan Chaturvedi</b> (Retd.)	<b>Member</b>
Hon'ble Justice <b>Smt. Rekha Kumari</b> (Retd.)	<b>Member</b>

The reconstitution will come into effect with the issue of the notification

By order of the Governor of Bihar,

**Ranjan Kumar Sinha**, *Additional Secretary*.

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 18-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 974--- I, Dr. Sunita Singh, aged-54 year, daughter of Dr. Hardeo Narayan Sinha and wife of Dr. Arjun Kumar Singh, resident of A/39, P.C. Colony, Kankarbagh, Patna will be known as Dr. Sunita Kumari from today onwards Aff.- 99. dated- 17.05.18.

Dr. Sunita Singh.

No. 975---I **NUZHAT NAZAR** D/O:-NIYAZ AHMAD W/O:-SULTAN AHMAD R/O:-vill.-Chahatpur, Dehti, P.S-Palasi, Distt.-Araria do hereby solemnly affirm and declare that my passport was issued according to my voter ID name as **NUJHAT NAJAR**. Which is wrong. Instead of that my name in all the documents i.e. certificate from matriculation to M.A. as well as Aadhar card is **NUZHAT NAZAR**. This is true. Affidavit No:- 429/2018 dated 11.04.2018, NOTARY ARARIA.

**NUZHAT NAZAR.**

No. 995---I, Sanjeev Kumar Sinha, S/O Late Pradyumna Prasad, Chief Manager, State Bank of India and R/O Patna, Bihar & Native Place-Gola Road, Muzaffarpur 842001, Bihar, do solemnly hereby affirm and declare that my old name is Sanjeev Kumar Singh and my new name is Sanjeev Kumar Sinha from 08-06-2018. The both names are same person and one person.

Sanjeev Kumar Sinha.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 18-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# बिहार गजट

## का

## पूरक(अ0)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

12 जुलाई 2018

सं० 3/आ01-177/2016-476—श्रीमती नीलम कुमारी, तत्कालीन वरीय व्याख्याता, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, गर्दनीबाग, पटना—सम्प्रति—सेवानिवृत्त के विरुद्ध निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार पटना के पीत पत्र सं०-1664 दिनांक 13.10.2016 द्वारा प्रेषित आरोप पत्र प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों यथा सी0बी0आई0 के जॉच प्रतिवेदन में नियुक्ति अनियमित पाये जाने संबंधी आरोपों के लिए श्रीमती कुमारी के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय संकल्प सं०-768 दिनांक 23.11.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री अरशद फिरोज, उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना—सह—संचालन पदाधिकारी के पत्रांक—उ0स0को0—45 दिनांक 31.03.2018 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्रीमती कुमारी के विरुद्ध उपलब्ध कराये गए प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की पुष्टि की गयी।

3. श्रीमती कुमारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक 282 दिनांक 11.04.2018 द्वारा श्रीमती कुमारी से कारण पृच्छा जवाब की मांग की गयी।

4. श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, श्रीमती कुमारी के बचाव अभिकथन, श्रीमती कुमारी के बचाव अभिकथन पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्राप्त मंतव्य, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं श्रीमती कुमारी के कारण पृच्छा जवाब के सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया की श्रीमती कुमारी की नियुक्ति सक्षम चयन समिति द्वारा नहीं की गयी एवं साक्षात्कार के संबंध में भी सक्षम चयन समिति की कार्रवाई उपलब्ध नहीं है। श्रीमती कुमारी के नियुक्ति के पूर्व कोई विज्ञापन किसी समाचार पत्र या नियोजनालय के माध्यम से प्रकाशित नहीं किया गया तथा आरक्षण रॉस्टर का भी अनुपालन नहीं किया गया। श्रीमती कुमारी के प्रथम नियुक्ति के समय प्रशिक्षित भी नहीं थी तथा ग्रीष्मावकाश के पूर्व इनकी सेवा समाप्त होने के बाद इन्होंने 1980 में बेसिक ट्रेनिंग प्राप्त किया। इसके बाद विद्यालय निरिक्षिका, पटना सह नालन्दा द्वारा दिनांक 06.07.1981 को श्रीमती कुमारी की पुनर्नियुक्ति की गयी। इस प्रकार श्रीमती कुमारी की नियुक्ति की जॉच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जॉच के दायरे में थी। श्रीमती कुमारी की नियुक्ति की जॉच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गयी तथा श्रीमती कुमारी की नियुक्ति को अनियमित पाया गया। श्रीमती कुमारी सी0बी0आई0 के जॉच रिपोर्ट के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपस्थापित करने में विफल रही, जिससे सी0बी0आई0 के रिपोर्ट में प्रस्तुत तथ्य प्रमाणित होते हैं। श्रीमती कुमारी की नियुक्ति ही अनियमित पायी गई है, जो गंभीर कदाचार के श्रेणी में आता है।

5. अतएव श्रीमती कुमारी को निम्न दंड संसूचित करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है।

(क) श्रीमती नीलम कुमारी, सेवानिवृत्त वरीय व्याख्याता, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय गर्दनीबाग, पटना का पेंशन, उपादान एवं उपार्जित अवकाश नकदीकारण शून्य किया जाता है।

(ख) भविष्य निधि में संचित राशि एवं गुप बीमा योजना में संचित राशि का भुगतान इन्हें अनुमान्य होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुशील कुमार, निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव।

सं० कारा/नि०को०(विधि)-10-22/2015(अंश)-5035

**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)**

**संकल्प**

**19 जुलाई 2018**

श्री रामचन्द्र महतो, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन उपाधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त काराधीक्षक) के विरुद्ध उनके विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर में पदस्थापन काल में दवा आपूर्ति के मामले (वित्तीय वर्ष-2012-13) में ससमय विपत्रों की शुद्धता की जाँच नहीं करने, विसंगति पाये जाने पर वरीय पदाधिकारी से मार्गदर्शन नहीं माँगने एवं आवंटन को प्रत्यर्पित करने में सहभागिता निभाने तथा अनुशासनहीनता बरतने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7141 दिनांक 28.11.2016 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री महतो दिनांक 30.09.2017 को सेवानिवृत्त हो गये। फलस्वरूप विभागीय आदेश ज्ञापांक 5713 दिनांक 05.10.2017 के द्वारा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30.09.2017 के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

3. विभागीय जाँच आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक 521 अनु० दिनांक 10.10.2017 से प्राप्त विभागीय जाँच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना के जाँच प्रतिवेदन में श्री महतो के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री महतो के विरुद्ध गठित आरोप सत्य प्रतीत होते हैं। तद्आलोक में विभागीय ज्ञापांक 7306 दिनांक 26.12.2017 द्वारा संचालन पदाधिकारी के अधिगम से कतिपय बिन्दुओं पर असहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री महतो से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

4. तद्आलोक में श्री महतो के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर में उन्होंने दिनांक 15.02.2013 को उपाधीक्षक के पद पर योगदान कर प्रभार ग्रहण किया। दवाओं की संचिका का प्रभार दिनांक 06.03.2013 को दिया गया तथा दो दिनों में दिनांक 08.03.2013 को दवाओं के समस्त बकाया विपत्रों का उपस्थापन अधीक्षक के समक्ष कर दिया गया। विभाग द्वारा अध्यायना से काफी अधिक राशि का अप्रत्याशित आवंटन मो०-13,00,000=00 (तेरह लाख) रुपये दिए जाने का कारण उन्हें ज्ञात नहीं हुआ तथा उक्त आवंटन आदेश में मेसर्स कृष्णा इन्टरप्राइजेज, पटना के बकायों का भुगतान किया जाय, वैसा कोई निदेश अंकित नहीं था। फिर भी अधीक्षक के मौखिक आदेश कि, दवाओं के क्रयोंपरान्त विभागीय ज्ञापांक 6952 दिनांक 14.11.2017 को क्षांत करने का आदेश घटनोत्तर प्राप्त कर लिया गया है, उनके द्वारा मेसर्स कृष्णा इन्टरप्राइजेज, पटना के नाम से विपत्र संख्या-362/12-13 जिसकी राशि मो० 02,94,200=00 रुपये एवं विपत्र सं०-368/12-13 जिसकी राशि मो०-03,39,665=00 रुपये कंटेन्जेन्ट रजिस्टर पेज नं०-34 एवं 36 तथा आवंटन पंजी, बिल रजिस्टर (विपत्र पंजी) में अंकित है, को उपस्थापित किया गया।

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि विपत्रों की जाँच के क्रम में ही पाया गया कि मेसर्स कृष्णा इन्टरप्राइजेज, पटना द्वारा उपस्थापित विपत्र, जो मेसर्स कर्नाटका एन्टीबायोटिक्स एवं फार्मास्युटिकल्स लि०, बंगलोर के प्राधिकृत प्रतिनिधि एवं उक्त अवधि में उक्त फर्म बिहार राज्य के काराओं में दवा आपूर्ति के लिए अनुशंसित फर्मों की सूची में नहीं है, जिसे अधीक्षक के संज्ञान में लाया गया था और अधीक्षक के द्वारा घटनोत्तर क्षांत संबंधी आदेश प्राप्त कर लिए जाने की जानकारी देने के बाद आश्वस्त होकर ही भुगतान के लिए विपत्र प्रस्तुत किया था। दवाओं के अन्य सभी विपत्र, जो इन दोनों विपत्रों के आगे-पीछे थे, को भुगतान हेतु हस्ताक्षरित किया गया एवं मेसर्स कृष्णा इन्टरप्राइजेज, पटना के विपत्रों को हस्ताक्षरित न करने के बाद शेष राशि को विभागीय निदेश के अनुपालन में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के निदेश पर विभाग को प्रत्यर्पित किया गया। यदि अधीक्षक उक्त विपत्र को पारित करना विधिसम्मत मानते तो उनके द्वारा उन्हें उसी पंजी या अपने मिनट बुक से आदेश दे सकते थे, जो नहीं किया गया। फलतः शेष आवंटन प्रत्यर्पण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था।

5. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, संचिका में उपलब्ध अभिलेख एवं श्री महतो द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जवाब की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि उनका बचाव बयान स्वीकार करने योग्य नहीं है। उनके जवाब में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर कर उल्लेखित किया गया है जो आरोप से बचने का प्रयास मात्र है। इस संबंध में विभाग के स्तर पर त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया था और समिति द्वारा भी श्री महतो को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया था। यह भी स्पष्ट होता है कि श्री महतो द्वारा अपने विभागीय कार्यों में लापरवाही बरती गयी है। अतः श्री महतो का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार्य नहीं है।

6. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री महतो के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (ए) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया :-

“ चार (04) वर्षों तक 15 % पेंशन की राशि के कटौती का दंड।”।

7. उपर्युक्त विनिश्चयी दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1444 दिनांक 06.03.2018 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1018 दिनांक 12.07.2018 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

8. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रामचन्द्र महतो, तत्कालीन उपाधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त काराधीक्षक) को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (ए) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-

“ चार (04) वर्षों तक 15 % पेंशन की राशि के कटौती का दंड।”।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजीव वर्मा, अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

सं० कारा/नि०को०(अधी०)-01-01/2018-4920

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

17 जुलाई 2018

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 30.08.2017 को मंडल कारा, कटिहार में बंदी के साथ की गई मारपीट की घटना का विडियो दिनांक 01.09.2017 को सोशल मिडिया में वायरल होने तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर एवं न्यूज चैनलों में प्रसारित घटना के संदर्भ में श्री राम सुमेर शर्मा, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार (सम्प्रति निलंबित काराधीक्षक) के द्वारा लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है।

श्री शर्मा का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार (सम्प्रति निलंबित काराधीक्षक) के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री शर्मा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजीव वर्मा, अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 18-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>